दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, मंगलवार 28 अप्रैल 2020 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-02, अंक- 208

महत्वपूर्ण एवं खास

खाद्य मंत्री भगत ने की धान कस्टम मीलिंग की समीक्षा

रायपुर। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आज यहां खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में प्रदेश के किसानों से खरीदे गए धान की कस्टम मीलिंग की समीक्षा की। भगत ने प्रदेश के उपार्जन केन्द्रों में शेष बचे धान का शीघ्र कस्टम मीलिंग कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में समितियों द्वारा 83 लाख 67 हजार मीट्रिक टन धान खरीदी गई है। इसमें से 96 प्रतिशत धान का उठाव उपार्जन केन्द्रों से हो चुका है और 3 लाख 44 हजार मीट्रिक टन धान उठाव के लिए शेष है। बताया गया कि कस्टम मिलिंग के लिए मिलरों को 50.69 लाख मीट्रिक टन धान उपलब्ध कराया गया था। इसके विरूद्ध मिलरों द्वारा 28.98 लाख मीट्रिक टन चावल जमा किया जा चुका है। शेष धान का कस्टम मीलिंग प्रगति पर है। बैठक में खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, विशेष सचिव अलेक्स पाल मेनन, एम.डी. मार्कफेड श्रीमती शम्मी आबिदी एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे।

राज्य में अब तक एक करोड़ से अधिक राशि के महुआ फूल का संग्रहण

रायपुर। राज्य में चालू सीजन के दौरान अब तक एक करोड़ 13 लाख रूपए की राशि के 3 हजार 752 क्विंटल महुआ फूल (सूखा) का संग्रहण हो चुका है। राज्य में इस वर्ष 2 लाख 65 हजार 75 क्विंटल महुआ फूल (सूखा) के संग्रहण होने का लक्ष्य निर्धारित है। उल्लेखनीय है कि राज्य में ग्रामीण वनवासियों के हित के लिए राज्य शासन द्वारा हाल ही में अहम निर्णय लेते हुए महुआ फूल के संग्रहण दर को 17 रूपए से बढ़ाकर 30 रूपए प्रति किलोग्राम कर दिया गया है।

आबकारी विभाग द्वारा दस होटलों में आकस्मिक छापेमारी

रायपुर। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को दृष्टि में रखते हुए राज्य शासन के निर्देशानुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें, समस्त बार और क्लब को बंद किया गया है, जिसका कठोरता से पालन कराया जा रहा है। इस विषय में कतिपय शिकायतें प्राप्त हो रही थीं कि कुछ बारों द्वारा अवैध रूप से मदिरा का विक्रय किया जा रहा है। प्राप्त शिकायतों को आबकारी विभाग द्वारा गंभीरता से लिया गया तथा आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार 26 अप्रैल को राज्य स्तरीय उड़नदस्ता तथा संभागीय उड़नदस्ता रायपुर की टीमों द्वारा संयुक्त रूप से रायपुर शहर में स्थित होटल ग्रैंड इम्पेरियाय, द लिविंग रूम कैफेय क्यू लखनवी रेस्टॉरेंटय 3 किंग्स रेस्टॉरेंटय शीतल इंटरनेशनलय ऑर्चिड बारय मोनू बारय होटल सिमरनय होटल पुनीतय होटल सी रॉकय कुल 10 स्थानों पर आकस्मिक दबिश दे कर जांच की गई। जांच में उपरोक्त 10 स्थानों में से 06 स्थान पूर्णतः बंद पाए गए तथा शेष 04 स्थानों की जांच में कोई संदिग्ध गतिविधि दर्शित नहीं हुई। समस्त स्थानों पर स्टॉक रूम विधिवत सील पाए गए जो कि बंदी आदेश के परिपेक्ष में लगाए गए थे। उपरोक्त जांच के पूर्व छद्म क्रेता के माध्यम से मदिरा विक्रय का परीक्षण भी कराया गया जिसमें किसी भी स्थान से मदिरा का विक्रय किया जाना नहीं पाया गया।

विभिन्न जिलों के करीब हजार बच्चे आज कोटा से रायपुर पहुंचेगे

रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पहल पर राजस्थान के कोटा में लॉकडाउन के दौरान फंसे छतीसगढ के छात्र-छात्राओं को वापसी का मार्ग प्रशस्त हो गया है। ये बच्चें कोटा से कल रात रवाना हो चुके हैं । ऐहतियात के तौर पर इन बच्चों को राज्य के दूसरे जिलों में 14 दिनों के क्वेरेंटाइन अवधि में रखा जायेगा। रायपुर में प्रदेश के विभिन्न जिलों के करीब एक हजार बच्चे रूकेगे। इन बच्चों के कल 28 अप्रैल के सुबह रायपुर पहुंचने की संभावना है। कलेक्टर डॉ एस भारती दासन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आरिफ शेख ने आज इन बच्चों के ठहरने की दृष्टि से रायपुर में चिन्हित किये गए प्रयास आवासीय विद्यालय बालक छात्रावास सड्डु, प्रयास आवासीय विद्यालय बालिका छात्रावास गुढियारी , ज्ञान गंगा स्कूल छात्रावास और एन एच गोयल स्कूल छात्रावास का अवलोकन किया। उन्होंने यहां बच्चों के लिए रूकने के लिए कमरों , रसोई , शौचालय तथा अन्य व्यवस्थाओं का मुआयना किया।

पीएम ने की विद्युत,नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा

» समीक्षा बैठक में बिजली क्षेत्र से जुड़ी नीतिगत पहलों पर चर्चा की गई

नई दिल्ली,(आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि डिस्कॉम समय-समय पर अपने प्रदर्शन मापदंडों को प्रकाशित करें, ताकि लोगों को यह पता चल सके कि उनकी डिस्कॉम का प्रदर्शन समकक्ष कंपनियों की तुलना में कैसा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा बैठक में बिजली क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं के निवारण हेतु की गई विभिन्न नीतिगत पहलों पर चर्चा की गई, जिनमें संशोधित टैरिफ नीति और बिजली (संशोधन) विधेयक 2020 भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने बिजली क्षेत्र की परिचालन क्षमता में वृद्धि और वित्तीय निरंतरता या स्थायित्व में बेहतरी सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ता संतुष्टि बढ़ाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। उन्होंने यह बात रेखांकित की कि विद्युत सेक्टर, विशेष रूप से बिजली वितरण क्षेत्र में जो समस्याएं हैं वे सभी क्षेत्रों और राज्यों में एक जैसी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय को सभी राज्यों के लिए ठीक एक जैसा ही समाधान या सॉल्यूशन की तलाश करने के बजाय प्रत्येक राज्य को अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए राज्य-विशिष्ट समाधानों को प्रस्तुत करना चाहिए।प्रधानमंत्री ने विद्युत मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि विद्युत वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) समय-समय पर अपने प्रदर्शन मापदंडों को प्रकाशित करें, ताकि लोगों को यह पता चल सके कि उनकी डिस्कॉम का प्रदर्शन समकक्ष कंपनियों की तुलना में कैसा है। उन्होंने इस बात पर भी विशेष जोर दिया कि बिजली क्षेत्र में उपकरणों का उपयोग 'मेक इन इंडिया' के अनुरूप होना चाहिए। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने सोलर वाटर पंपों से लेकर विकेन्द्रीकृत सौर शीत भंडारणों तक की कृषि क्षेत्र की पूरी आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने रूफटॉप सोलर के लिए भी अभिनव मॉडल पर विशेष बल दिया और इसके साथ ही यह इच्छा जताई कि प्रत्येक राज्य में कम-से-कम एक शहर (या तो राजधानी शहर या कोई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल) ऐसा हो, जो रूफटॉप सौर ऊर्जा के उत्पादन के माध्यम से पूरी तरह से सौर शहर हो। बैठक के दौरान भारत में इंगोट, वेफर, सेल और मॉड्यूल के निर्माण का अनुकूल परिवेश विकसित करने पर भी विशेष जोर दिया गया, जो विभिन्न तरह के अन्य लाभ प्रदान करने के अलावा रोजगार सृजन में भी मददगार साबित होगा। प्रधानमंत्री ने 'कार्बन मुक्त लद्दाख' की योजना में तेजी लाने की इच्छा जताई और इसके साथ ही सौर एवं पवन ऊर्जा का उपयोग करके तटीय इलाकों में पेयजल आपूर्ति पर विशेष बल दिया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर कोरोना से बचाव और रोकथाम, लॉक डाउन के संबंध में आगे की रणनीति पर विचार-विमर्श किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कान्फ्रेंस में शामिल हुए। स्वास्थ्य मंत्री टी. एस. सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव आर.पी. मण्डल, पुलिस महानिदेशक डी.एम. अवस्थी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, स्वास्थ्य विभाग की सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, मुख्यमंत्री की उप सचिव सुश्री सौम्या चौरसिया इस अवसर पर उपस्थित थीं।

मुख्यमंत्री राहत शिविर बना आजीविका का केंद्रः 631 श्रमिकों को मिला रोजगार

रायपुर । कोरोना वायरय (कोविड-19) महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के दौरान भी मुख्यमंत्री राहत शिविर आजीविका का केन्द्र बन गया है। राहत शिविर में रूके श्रमिकों के लिए शासन द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वस्थ्य श्रमिक, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खाली समय में मेहनत कर अतिरिक्त आमदनी भी अर्जित कर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि सूरजपुर जिले में जिला प्रशासन द्वारा दीगर राज्य एवं अन्य जिलों से फंसे लगभग 631 श्रमिकों को 31 राहत केंद्रों में अतिथि की तरह ठहराया गया है। यहां अतिथि के रूप में उनकी देखभाल करने के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है।

राहत शिविर में रूके सभी श्रमिकों को राज्य शासन जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप भोजन, रहने के लिए पूर्ण व्यवस्था के साथ-साथ खेल सामग्री जैसे लूडो, कैरम, टीवी आदि प्रदान की गई है। श्रमिकों द्वारा नियमित रूप से योग भी किया जा रहा है। बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था भी सुचारु रुप से चल रही है।

इन शिविरों में रुके हुए श्रमिकों को उनकी दैनिक मजदूरी की जो आर्थिक क्षति हो रही है उसकी पूर्ति के लिए जिला प्रशासन ने विशेष पहल करते हुए इन्हें दैनिक आजीविका के कार्य उपलब्ध करा रहे हैं। शिविर में श्रमिक द्वारा बांस के ट्री गार्ड का निर्माण किया जा रहा है। जिसको कि वन विभाग द्वारा त्वरित क्रय किया जा रहा है। इसके लिए श्रमिकों को आवश्यक बांस की उपलब्धता वन विभाग द्वारा कराए जाने के साथ ही कार्य प्रारंभ होने से पूर्व मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण भी दिया गया है। जिसके बाद इनके द्वारा सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए ट्री गार्ड बनाने में शिद्दत के साथ जुट गए हैं। प्रशिक्षित श्रमिकों द्वारा ट्री गार्ड निर्माण पर मात्र दो दिवस में ही श्रमिकों को प्रशासन द्वारा लगभग 30 हजार रूपए से अधिक का भुगतान किया गया है। प्रत्येक श्रमिक द्वारा दिन में लगभग 350 से 400 रूपए तक की आमदनी अर्जित की जा रही है। इस विशेष पहल से मुख्यमंत्री राहत शिविर न केवल राहत शिविर वरन् एक मुख्यमंत्री आजीविका केंद्र के रूप में तब्दील हो गया है। यहां ठहरे अतिथियों में अत्यंत खुशी का माहौल है और अब उन्हें अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करते हुए और बेहतर तरीके से समय बिताने का अवसर प्राप्त हो गया है। इन्ही में शामील मध्य प्रदेश बालाघाट जिले के एक अतिथि भोजलाल डोमार को जब उनकी मेहनत की कमाई हुई रकम हाथ में मिली तो उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद करते हुए कहा कि लॉकडाउन में जब हम शिविर में आएं थे, तो यह नहीं सोंचा था कि राहत शिविर में हमें काम मिल जाएगा और इससे आमदनी भी मिलेगी। वास्तव में यह सपना छत्तीसगढ़ सरकार के जरिए पूरा भी हो रहा है।

भोजलाल डोमार ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार हमारा और हमारे परिवार का न केवल सुरक्षा का ध्यान रखा बल्कि हमारे आजीविका के लिए काम का अवसर उपलब्ध कराया है। अब हम यहां मुख्यमंत्री राहत शिविर के खुशनुमा यादों के साथ कमायें हुए पैसों को लेकर अपने घर जायेंगें। डोमार ने खुशियों से भरे लफ्जों में जिला प्रशासन के अधिकारियों को अपने घर बालाघाट आने का आमंत्रित किया। इस दौरान अन्य श्रमिकों ने भी कहा कि जब हम लॉकडाउन के बाद अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। तब यह न केवल खुशनुमा यादें बल्कि अपने साथ अपनी कमाई हुई रकम भी साथ लेकर जाएंगे और बेहतर रूप से आर्थिक सुदृढ़ बनकर अपने घर पहुंचेंगे।

रिस्दा में लहलहाती मूंग की फसल से गदगद हैं किसान

रायपुर । राज्य शासन का महत्वाकांक्षी नरवा, गरूवा, घुरूवा और बारी योजना के अंतर्गत बिलासपुर जिले के मस्तूरी विकासखंड के ग्राम रिस्दा में 18 किसानों द्वारा 65 एकड़ में ग्रीष्मकालीन मूंग की बोनी की गई है। मूंग की लहलहाती फसलों को देखकर किसान बेहतर उत्पादन के लिए गदगद हैं। ग्राम रिस्दा में मूंग की फसल वर्तमान में 15 दिन से अधिक हो चुकी है। किसानों को समय-समय पर कृषि विभाग के मैदानी अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा समसामयिक सलाह एवं मार्गदर्शन दिया जा रहा है। साथ ही कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा खेतों में जाकर फसलों का अवलोकन भी किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी नरवा, गरूवा, घुरूवा और बारी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम चरण में चयनित 97 गौठानों के ग्रामों में जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में

प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न लाभदायी फसलों के उत्पादन के लिये विशेष जोर दिया गया है। वहीं पशुओं के खुला छोड़ने पर प्रतिबंध लगने से किसान निश्चिंत होकर खेती कर रहे हैं। अब उन्हें अपने फसलों का पशुओं से हानि होने का कोई डर नहीं है। गौठानों में चारा विकास के साथ ही गेहूं, चना, मटर, अलसी, राई सरसों आदि फसलों के बोनी हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। वर्ष 2019-20 के रबी सीजन में चयनित गौठानों के ग्रामों में विभागीय योजनाओं के तहत एक हजार 291 हेक्टेयर में रबी फसलों की बोनी की गई।

चालू रबी सीजन में 57,078 हेक्टेयर में सिंचाई का लक्ष्य पूर्णता की ओर

राज्य में रबी फसलों की सिंचाई के लिए जलाशयों से जारी है जलापूर्ति

रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप राज्य में रबी फसलों की सिंचाई के लिए जल संसाधन विभाग के जलाशयों, बांधों एवं बैराजों से जलापूर्ति जारी है। इस रबी सीजन में 57 हजार 78 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए जलापूर्ति का लक्ष्य पूर्णता की ओर है। मई के प्रथम सप्ताह तक रबी फसलों की सिंचाई के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि रबी फसलों की सिंचाई का यह लक्ष्य बीते वर्ष की तुलना में दोगुना से अधिक है। गतवर्ष रबी सीजन में 28 हजार हेक्टेयर में जलापूर्ति की गई थी।

जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि राज्य में रबी की सिंचाई की क्षमता में दोगुना की बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण यह है कि बीते एक सालों के दौरान जल संसाधन विभाग द्वारा सिंचाई की पुरानी योजनाओं का जीर्णोद्धार एवं उन्नयन कर उनकी सिंचाई क्षमता को पुर्नस्थापित किया गया, जिससे राज्य में रबी की सिंचाई क्षमता 28 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 75 हजार हेक्टेयर हो गई और इसका लाभ भी राज्य के किसानों को मिलने लगा है। जल संसाधन विभाग के प्राप्त जानकारी अनुसार इस वर्ष राज्य के 18 जिलों में रबी फसलों के 57 हजार 78 हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों की मांग के अनुरूप समय-समय पर विभाग जलाशयों एवं बांधों से पानी छोड़कर सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराया जा रहा है। बालोद जिले में 9104 हेक्टेयर, दुर्ग में 397 हेक्टेयर, राजनांदगांव में 1651 हेक्टेयर, महासमुंद में 1196 हेक्टेयर, रायपुर में 2050 हेक्टेयर, धमतरी में 11 हजार 166 हेक्टेयर, बिलासपुर में 1191 हेक्टेयर, कोरबा में 83 हेक्टेयर, रायगढ़ में 1322 हेक्टेयर, जांजगीर-चांपा में 11 हजार हेक्टेयर, सरगुजा में 5551 हेक्टेयर, बलरामपुर-रामानुजगंज में 889 हेक्टेयर, सूरजपुर जिले में 1765 हेक्टेयर, कोरिया जिले में 4983 हेक्टेयर,

संग्राहकों द्वारा लगभग 73 हजार क्विंटल वनोपजों का संग्रहण

वनोपजों के संग्रहण से वनवासी-ग्रामीणों के लिए बढ़े रोजगार के अवसरः वन मंत्री अकबर

रायपुर। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि कोरोना लॉकडाउन के कारण संकट की इस घड़ी में सरकार द्वारा लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी और नगद भुगतान की प्रक्रिया से वनांचल के वनवासी-ग्रामीणों को काफी राहत मिल रही है। साथ ही वनोपजों के संग्राहकों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ गए हैं।

प्रदेश में चालू सीजन के दौरान अब तक एक लाख 32 हजार 272 संग्राहकों द्वारा लगभग 21 करोड़ रूपए की राशि के 72 हजार 727 क्विंटल वनोपजों का संग्रहण हो चुका है। इनमें लक्ष्य के मुताबिक सबसे अधिक संग्रहण वाले 5 वनमण्डलों में नारायणपुर, दंतेवाड़ा, केशकाल, दक्षिण कोण्डागांव तथा बालोद वनमण्डल शामिल है। अब तक नारायणपुर वनमण्डल में लक्ष्य का 43 प्रतिशत अर्थात् 3 करोड़ 36 लाख

रूपए के 10 हजार 995 क्विंटल, दंतेवाड़ा में 26 प्रतिशत अर्थात् 3 करोड़ 10 लाख के 10 हजार 68 क्विंटल तथा केशकाल में लक्ष्य का 20 प्रतिशत अर्थात् एक करोड़ 94 लाख रूपए के 6 हजार 571 क्विंटल वनोपजों का संग्रहण हो चुका है। इसके अलावा वनमण्डल दक्षिण कोण्डागांव में लक्ष्य का 20 प्रतिशत अर्थात् 3 करोड़ 37 लाख रूपए की राशि के 11 हजार 203 क्विंटल और वनमण्डल बालोद में लक्ष्य का 18 प्रतिशत अर्थात् 19 लाख रूपए की राशि के 900 क्विंटल वनोपजों का संग्रहण किया गया है।

इसी तरह राज्य में अब तक संग्रहित वनोपजों से लगभग एक लाख 32 हजार संग्राहक लाभान्वित हुए हैं। इनमें वनमण्डलवार लाभान्वित संग्राहकों में नारायणपुर में 11 हजार 109, दंतेवाड़ा में 22 हजार 496, केशकाल में 8 हजार 489, दक्षिण कोण्डागांव में 13 हजार 721 तथा बालोद में एक हजार 294 शामिल है। वनमण्डलवार जगदलपुर में 12 हजार 345, पूर्व भानुप्रतापपुर में 3 हजार 286, कांकेर में 6 हजार 727, सुकमा में 10 हजार 352, पश्चिम भानुप्रतापपुर में 4 हजार 68, खैरागढ़ में एक हजार 729, धमतरी में एक हजार 672 तथा बीजापुर में 10 हजार 551 संग्राहक लाभान्वित हुए हैं। वनमण्डलवार कवर्धा में 552, रायगढ़ में 980, कोरबा में 7 हजार 32, राजनांदगांव में एक हजार 824 तथा गरियाबंद में एक हजार 776 संग्राहकों द्वारा वनोपजों का संग्रहण किया गया है।

वनमण्डलवार बिलासपुर में 969, बलौदाबाजार में 707, कटघोरा में 949, सूरजपुर में 3 हजार 175, कोरिया में 515, मरवाही में एक हजार 63, तथा सरगुजा में 509 संग्राहक लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा वनमण्डलवार जशपुर में एक हजार 176, महासमुंद में 188, बलरामपुर में एक हजार 956, धरमजयगढ़ में 617 और मनेन्द्रगढ़ में 445 संग्राहकों द्वारा वनोपजों का संग्रहण किया गया है। राज्य में चालू वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत संग्रहित लघु वनोपजों में इमली (बीज सहित), पुवाड़ (चरोटा), महुआ फूल (सूखा), बहेड़ा, हर्रा, कालमेघ, धवई फूल (सूखा), नागरमोथा, इमली फूल, करंज बीज तथा शहद शामिल हैं। इसके अलावा बेल गुदा, आंवला (बीज रहित), रंगीनी लाख, कुसुमी लाख, फुल झाड़ु, चिरौंजी गुठली, कुल्लू गोंद, महुआ बीज, कौंच बीज, जामुन बीज (सूखा), बायबडिंग, तथा साल बीज शामिल हैं।